B-3

L-14

---प्रत्यक्ष कर---

प्रत्यक्ष कर लगाते समय यह देखना आवश्यक है कि उनकी दर उचित हो। ध्यान देने योग्य है कि कर की दर को लगातार बढ़ाने से राजस्व बढ़ने की बजाय कम होने लगता है। इस सन्दर्भ में निम्न चित्र पर विचार किया जा सकता है।

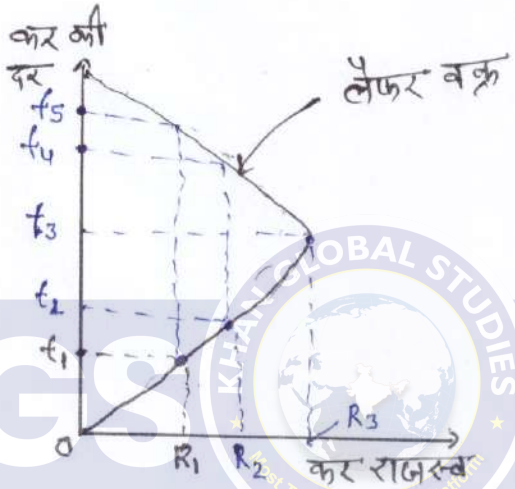

उपर्युक्त चित्र को देखने से पता लगता है कि जैसे-जैसे शुरूआत में कर की दर को बढ़ाया जाता है तो राजस्व भी बढ़ता है लेकिन यह कर की t_3 दर तक होता है। यदि इसके बाद भी कर की दर को बढ़ाया जाता है तो राजस्व कम होने लगता है।

अन्य बातों के अलावा, इसका एक बड़ा कारण यह होता है कि कर की अधिक ऊँची दरों पर लोग काम (work) के बजाय आराम (Leisure) को अधिक वरीयता देने लगते हैं। इसके कारण लोगों की आय कम होने लगती है और कर राजस्व भी कम होने लगता है।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform

⟹ पूंजीगत प्राप्तियां (Capital Receipts)

- सरकार को मिलने वाली ऐसी आय जिसे प्राप्त करने के लिए या तो सार्वजनिक सम्पत्तियों को कम करना पड़े या सार्वजनिक देयताओं को बढ़ाना पड़े। इसके मुख्य उदाहरण निम्नलिखित हैं:-

1. विनिवेश (Disinvestment)
   ↳ सरकारी उपक्रमों की हिस्सेदारी बेचना।

2. ऋणों की वसूली (Recovery of Loans)

3. बाजार से उधार (Market Borrowings)
   - आन्तरिक ⇓ रिजर्व बैंक
   - बाह्य ⇓ भारत सरकार

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

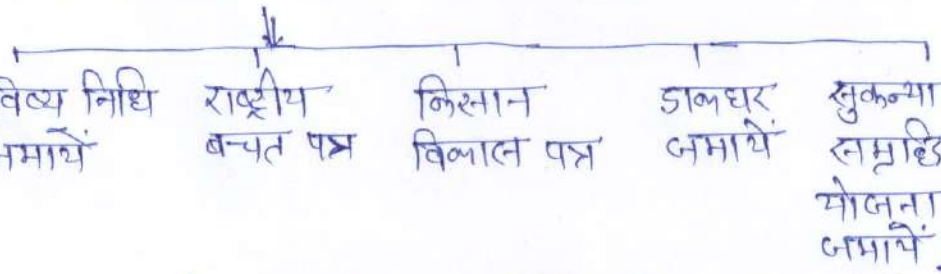

4. अन्य देयतायें : अल्प बचत संग्रहण
   - भविष्य निधि जमायें
   - राष्ट्रीय बचत पत्र
   - किसान विकास पत्र
   - डाकघर जमायें
   - सुकन्या समृद्धि योजना जमायें etc

Note- 1- उपर्युक्त पूंजीगत प्राप्तियों में 1 और 2 को NDCR (Non-Debt Capital Receipts) कहा जाता है।

2- आन्तरिक बाजार से उधार लेने के लिए RBI भारत सरकार की ओर से दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां (Dated G-Sec)- Govt. Securities) जारी करता है।
एक वर्ष से अधिक की समयावधि की G-Sec को दिनांकित G-Sec कहा जाता है।

⟹ सरकारी खर्च

- राजस्व खर्च
- पूंजीगत खर्च

राजस्व खर्च (Revenue Expenditure)

- ऐसे खर्च जिनसे न तो सार्वजनिक सम्पतियों का निर्माण होता है और न ही सार्वजनिक देयतायें कम होती हैं। इसके मुख्य उदाहरण निम्नलिखित हैं-

(i) ब्याज भुगतान
(ii) वेतन और पेंशन
(iii) सब्सिडी
(iv) लिखानों के ऋणों को माफ करना आदि।
(v) अनुदान (Grants)

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
KHAN SIR

पूंजीगत खर्च (Capital Expenditure या Capex)

- ऐसे खर्च जो या तो सार्वजनिक सम्पत्तियों का निर्माण करते हैं या सार्वजनिक देयताओं को कम करते हैं। इसके मुख्य उदाहरण निम्नलिखित हैं।-

1. राष्ट्रीय राजमार्ग, एयरपोर्ट आदि सार्वजनिक सम्पत्तियों का निर्माण।
2. ऋणों का पुनर्भुगतान (Repayment of Loans)
3. राज्य सरकारों, विदेशी सरकारों आदि को ऋण देना आदि।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
© KHAN SIR ©

⇒ भारत में सार्वजनिक खर्च का नया वर्गीकरण :-

⇒ इसे 2017-18 में लागू किया गया था। इसे रेखाचित्र द्वारा समझा जा सकता है।

- सार्वजनिक खर्च
  - Scheme Exp.
    - केन्द्र प्रायोजित योजनायें
      - Core of the Core Schemes (6)
      - Core Schemes (20)
      - Optional Schemes (2)
    - केन्द्रीय क्षेत्र की योजनायें
  - Non-Scheme Exp.

(6, 20, 2) — नीति आयोग के शिवराज सिंह उप-समूह की सिफारिशों के अनुसार